



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, १९ मार्च, १९९७/२४ फाल्गुन, १९१४

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(नियुक्ति-१)

अधिसूचना

शिमला-२, ३० दिसम्बर, १९९६

संख्या का० (नि०-१) (ए) (१) बी (२)-२/८७-ई० टी० ओ०.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या ७-५/७३-बी० पी० (नि०१), तारीख १५-३-७३ द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज, १९७३ में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (चतुर्थ संशोधन) रूलज, १९९६ है।

(२) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज, 1973 के नियम 9 (1) (2) में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज, 1973 के नियम 9(2)(1) के विद्यमान उपाबन्ध के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“The Committee shall consider from time to time the cases of officers eligible for appointment to the service who have opted for consideration for promotion excepting those officers who have been debarred from consideration in terms of Rule 17 and prepare two separate lists of officers according to the percentage fixed under clauses (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 7. Each list shall contain the names of the selected candidates twice the number of vacancies available at the time of selection and likely to occur during the next year for each category under clause (b) and (c) of sub-rule (1).”

3. हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज, 1973 के नियम 17 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज, 1973 के नियम 17 के विद्यमान उपाबन्ध के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“Notwithstanding anything to the contrary contained in any other Rule or instructions of the Government if a candidate on appointment to a particular post is unable for any reason other than the orders of the Government to join his appointment within three months from the date of receipt of orders or within the extension granted for joining on justifiable grounds, he/she shall be ineligible for appointment to the service (HPAS).”

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव ।

[Authoritative English text of this Department notification No. Per (A) (1) B (2)-2/87-ETO, dated 30-12-96 as required under Article 348 of the Constitution of India]

PERSONNEL DEPARTMENT (Appointment-I)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 30th December, 1996

No. Per (A)(1)B(2)-2/87-ETO.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 307 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, notified vide this Department notification No. 7-5/73-DP (Apptt.), dated the 15th March, 1973, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Administrative Service (Fourth Amendment) Rules, 1996.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Rule 9 (1) (2) (i) of the HPAS Rules, 1973.*—For the existing provisions of Rule 9 (2) (i) of the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973 the following shall be substituted :—

“The Committee shall consider from time to time the cases of officers eligible for appointment to the service who have opted for consideration for promotion excepting those officers who have been debarred from consideration in terms of Rule 17 and prepare two separate lists of officers according to the percentage fixed under clauses (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 7. Each list shall contain the names of the selected candidate twice the number of vacancies available at the time of selection and likely to occur during the next year for each category under clause (b) and (c) of sub-rule (1).”

3. *Amendment of Rule 17 (2) of HPAS Rules, 1973.*—For the existing provision of Rule 17 of HPAS Rules, 1973 the following shall be substituted :—

“Notwithstanding anything to the contrary contained in any other Rule of instructions of the Government if a candidate, on appointment to a particular post is unable for any reason, other than the orders of the Government to join his appointment within three months from the date of receipt of orders, or within the extension granted for joining on justifiable grounds, he/she shall be ineligible for appointment to the service (HPAS).”

By order,

Sd/-
Chief Secretary.

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-1, 3 मार्च, 1997

संख्या आयु० सी० ई० (3) 22/94.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्ययपर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा माजरा, जिला सिरमौर में मिनी हबल गार्डन के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन सहायता एवं उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), पाँवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-प्रजनन समाहर्ता, पांवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरण

जिला : सिरमौर	स्थान	खसरा नं०	तहसील : पांवटा साहिब रकबा (बीघों में)
	माजरा	166/2	3-14

आदेश द्वारा,

जे० पी० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 1 मार्च, 1997

संख्या जी०ए०डी०-सी० (पी०ए०) (4) 23/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप मंत्रियों को निःशुल्क सुसज्जित गृह के स्थान पर दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से तत्काल प्रभाव से देय भत्ता नियत करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of Government notification No. GAD-C (PA) (4)-23/94, dated 1-3-97 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st March, 1997

No. GAD-C(PA) (4)-23/94.—In exercise of the powers conferred by section 5 of The Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to fix an allowance at the rate of two thousand five hundred rupees per mensem in lieu of the free furnished house to the Deputy Ministers with immediate effect.

By order,
Sd/-

Financial Commissioner-cum-Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
(संसदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 1 मार्च, 1997

संख्या जी०ए०डी०सी (पी०ए०) (4)-22/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रियों को देय निःशुल्क सुसज्जित गृह के स्थान पर निम्नलिखित दरों पर तत्काल प्रभाव से देय भत्ता नियत करते हैं:—

- (i) प्रत्येक मंत्री जो मंत्रीमण्डल का सदस्य हो तीन हजार पांच सौ रुपये प्रति माह
- (ii) राज्य मंत्री तीन हजार रुपये प्रति मास।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित—
वित्तायुक्त एवं मन्त्रि।

[Authorised English text of Government notification No. GAD-C (PA) (4)-22/94, dated 1-3-1997 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Parliamentary Affairs Department)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 1st March, 1997

No. GAD-C (PA) (4)-22/94.—In exercise of the powers conferred by section 4 of The Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to fix an allowance in lieu of the free furnished house to the Ministers at the following rates with immediate effect:—

- | | |
|---|--|
| (i) every Minister who is a member of the Cabinet | Rupees three thousand five hundred per mensem. |
| (ii) a Minister of State | Rupees three thousand per mensem. |

By order,
Sd -

Financial Commissioner-cum-Secretary.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 मार्च, 1997

संख्या एच० एफ० डब्ल्यू० बी० (एफ) 4-1/81-III.—इस विभाग की समस्त अधिसूचना, तारीख

20-11-95 का अधिकरण करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 293 के प्रयोजन के लिए श्री ए० के० वासूजा, उप लोक विश्लेषक, संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट, जिला सोलन, हि० प्र० की (केवल ग्रस्त्याई रूप में) उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त, उनके अपने वेतनमान में, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए तत्काल प्रभाव से लोक हित में सहायक रासायनिक परीक्षक घोषित करते हैं।

इस नियुक्ति से, तथापि, उपरोक्त कार्य के लिए, उन्हें विशेष वेतन, मानदेय तथा वरिष्ठता इत्यादि का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

जे० पी० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. HFW-B(F)4-1/81-III, dated 3-3-97 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd March, 1997

No. HFW-B(F)4-1/81-III.—In supersession of this department notification of even number, dated 23th November, 1995, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare (purely temporarily) Shri A. K. Wasuja, Deputy Government Analyst, Composite Testing Laboratory, Kandaghat, District Solan, Himachal Pradesh as Assistant Chemical Examiner for the purposes of section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) for the whole of the State of Himachal Pradesh in addition to his own duties, in his own pay scale with immediate effect in public interest.

This appointment, however, shall not confer upon him any right for special pay, honorarium, seniority etc. for the above work.

By order,

J. P. NEGI,
Commissioner-cum-Secretary (Health).

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 मार्च, 1997

संख्या आई० एन० डी०-बी०(एफ)10-4/94.—क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में खड्डों और नदियों के तलों, पहाड़ी ढलानों में अव्यवस्थित और अन्धाधुन्ध खनन हो रहा है जिसके कारण खड्डों और नदियों के तलों के साथ भूमि कटाव, पहाड़ी ढलानों की स्थिरता को खतरा पैदा

हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण अनुत्क्रमणीय अवक्रमण की ओर जा रहा है और इससे क्षेत्र की दुर्बल परिस्थिति का सन्तुलन बिगड़ रहा है।

क्योंकि यह अव्यवस्थित, अन्धाधुन्ध खनन अधिकतर हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (कन्सेशन) रिवाइज्ड रूलज, 1971 के अधीन जारी किये गए अल्प-अवधि अनुज्ञापत्र द्वारा किया जा रहा है।

और क्योंकि जबकि इस अन्धाधुन्ध अव्यवस्थित खनन को जोकि राज्य के पर्यावरण का अनुत्क्रमणीय अवक्रमण कर रहा है और दुर्बल परिस्थिति को बिगाड़ रहा है, को नियन्त्रित करना अनिवार्य हो गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (कन्सेशन) रिवाइज्ड रूलज, 1971 के नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए क्षेत्र के निवासियों द्वारा वास्तविक निजी प्रयोग के लिए अल्प-अवधि अनुज्ञापत्रों पर अनुमति के सिवाये, पहाड़ी ढलानों और खड्डों, नदियों के तलों से अल्प-अवधि अनुज्ञापत्रों द्वारा रेत, पत्थरों, बजरी को निष्कासने पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध अधिरोपित करते हैं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि चूना पत्थर निकालने के लिए अल्प-अवधि अनुज्ञापत्र जारी न किए जायें और पूर्ववर्ती जारी किए गए ऐसे अनुज्ञापत्र रद्द समझे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

पी० एस० राणा,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English text of the Government notification No. Ind. B(F) 10-4/94, dated 5th March, 1997, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th March, 1997

No. Ind.-B(F)10-4/94.—Whereas it is felt that there has been haphazard and indiscriminate mining on the hill slopes, beds of rivers and khads in various parts of the Pradesh causing danger of disturbances to the stability of hill slopes, soil erosion along the beds of rivers and khads and consequently leading to irreversible degradation of environment and upsetting the fragile ecological balance of the region;

And whereas most of this haphazard and indiscriminate mining is being carried out through short term permits issued under Himachal Pradesh Minor Mineral (Concession) Revised Rules, 1971;

And whereas it is imperative to check the haphazard and indiscriminate mining which has been causing irreversible degradation of the environment and upsetting the fragile eco-system of the State;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him under sub-rule (2) of rule 5 of Himachal Pradesh Minor Mineral (Concession) Revised Rules, 1971, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to impose a total ban on extraction of sand, stones and bajri from the beds

of rivers, khads and hill slopes, through short term permits, except allowing such extraction on short term permits for bonafide personal use by the residents of the area.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that no short term permits shall be issued for extraction of limestone and any such permits issued earlier shall stand cancelled.

By order,

P. S. RANA,
Financial Commissioner-cum-Secretary (Ind.).

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 1st March, 1997

No. PBW(B & R) (B)-A(3)6-2/95.—In order to inspect the Aerial Ropeways in Himachal Pradesh, as required under section 12-A of H. P. Aerial Ropeways (Amended) Act, 1995 (Act No. 13 of 1995) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute an Expert Committee comprising of the following Engineers of H. P. PWD :—

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Superintending Engineer (D-1)
H. P. PWD., Shimla-1. | Chairman |
| 2. Superintending Engineer (Mech.)
H. P. PWD., Dhalli-171 012. | Member |
| 3. Superintending Engineer (Elect)
H.P. PWD., Kasumpti-171 009
or his representative. | -do- |
| 4. Inspector-cum-Executive Engineer (Mech.)
H P. PWD., Dhalli. | -do- |
| 5. Executive Engineer (Civil)
concerned Divisions. | Member Secretary. |

The notification dated 21st March, 1996 is hereby superseded.

By order,

P. S. RANA,
F. C.-cum-Secretary.

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th February, 1997

No. Rev. D(A) 2-1/94-SML.—In supersession of this department's notification of even number dated 27-11-1996 and in exercise of the powers vested in him under section 9 of H. P. Land Revenue Act, 1953 (Act No. 6 of 1954), and all other powers enabling him in this behalf,

the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Lal Ji Singh, Divisional Commissioner Kangra Division, at Dharamshala to perform the functions of Commissioner Shimla Division in appeal No. 120 of 1996 filed under section 9 of the Himachal Pradesh Public Pre uses and (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971, against the orders passed by the Collector, Directorate of Estates dated 2-8-1996 in case No. 36 against Shri V. K. Malik, IGP Railway and Traffic, Shimla.

By order,

Sd/-

Financial Commissioner-cum-Secy.

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

(Vocational and Industrial Training)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd March, 1997

No. Shram(Shr) 4/80.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by rule 56(d) of the F. R. is pleased to allow extension in service for a period of one year in favour of Shri N. M. Ramaul, Principal, I. T. I. Poanta, in the public interest. Shri N. M. Ramaul who was to retire from Govt. service on attaining the age of superannuation on 28th February, 1997 A. N. shall now retire from Govt. service on 28th February, 1998 (A. N.).

By order,

RAJWANT SANDHU,
Commissioner-cum-Secretary.

